Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)
Monthly Summary for the month of November, 2019

Important events for the month of November, 2019 are as follows:

(a) To recognize and honour young entrepreneurs and eco-system builders for their outstanding contribution in the field of entrepreneurship development, 4th Edition of National Entrepreneurship Awards Scheme was organized on 9th November, 2019 in which 36 Awards were conferred in two categories i.e. Enterprises (30 awards) and Eco-system Builder (6 awards). Winners were felicitated in a grand Award Ceremony, organized by MSDE at Pravasi Bhartiya Kendra, Delhi and presented with a Trophy, Certificate and a Cash Prize of Rs. 5 lakh (enterprises/individuals) and Rs. 10 lakh (organizations/institutes).

(b) MSDE has designed a Project on Entrepreneurship Development in six Holy cities of the country (Puri, Varanasi, Haridwar, Kollur, Pandharpur and Bodh Gaya) with an objective to enhance the entrepreneurial activities of the select cities through resumption of existing livelihood activities and/or by supporting existing enterprises to scale up.

(c) Joint Declaration of Intent between MSDE, Government of India and the Federal Ministry of Education and Research and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany on Cooperation in the field of Skill Development and Vocational Education and Training has been signed in New Delhi on 01st November, 2019.

(d) Joint Declaration of Intent between the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany and Siemens Limited, India and the MSDE, Government of India in the field of implementation of Dual VET (Vocational Education and Training) initiatives through applicable models has been signed in New Delhi on 01st November, 2019.

(e) Supplementary Agreement between the Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany and MSDE, Government of India in the field of Indo-German Programme for Vocational Education and Training (IG-VET Project) has been signed at New Delhi on 08th November, 2019.

(f) A meeting was held on 6th November 2019 at MSDE to discuss on Skilling in mountaineering and adventure related activities in the presence of officials from MSDE, Indian Monitoring Foundation (IMF), National Skill Development Corporation (NSDC), and Tourism and Hospitality Sector Skill Council (THSSC). Discussions were held on various points including: RPL programmes on selected job roles in mountaineering and adventure related activities shall be implemented on pilot basis under PMKVY (2016-20). THSSC in consultation with IMF will submit the detailed proposal on RPL in prescribed format under CSCM component of PMKVY (2016-2020). English, Employability and Entrepreneurship (3E) module for soft skilling and entrepreneurship will be the integral part of RPL program.

Institutions under Ministry of Defence should be onboarded under this RPL programme. IMF will start seeding the germination of ideas for creating professional bodies in the field on mountaineering and adventure related.

(g) Progress under Jan Shikshan Sansthan (JSS) scheme: For JSS courses, in addition to SC & ST categories of beneficiaries, fee has also been waived for Divyangjan and persons from weaker sections of Society, i.e. BPL. With a view to preserve and promote local traditional skills, all JSSs have been asked to identify at least one local traditional skill and run a minimum of four batches in a year for such skills.

(h) Progress under Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood (SANKALP) programme: 5th meeting of Project Screening Committee was held to evaluate and ascertain the suitability of the proposals submitted by stakeholders concerning SANKALP Programme. 5th meeting of Program Approval/ Appraisal Board was held to administer and steer the SANKALP Project. Video conferences were held with States/ UTs for reviewing the status of State Incentive Grant (SIG) baseline and submission of State proposal under SANKALP. State Incentive Grant was released to the States of Chattisgarh, Odisha, Tripura, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. The achievements against the Disbursement Linked Indicators (DLIs) 1 and 4 for the first two years was verified by the Independent Verification Agency and the Verification Report was shared with World Bank for unlocking of fund amounting to US $ 17,767,173/-.

****

<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

नवंबर, 2019 माह हेतु मासिक सारांश

<u>नवंबर, 2019 माह की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार है:</u>

(क) उद्यमशीलता विकास के क्षेत्र में युवा उद्यमियों तथा ईकोसिस्टम निर्माताओं को उनके बेहतर योगदान को मान्यता तथा सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार स्कीम का चौथा संस्करण 09 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें दो श्रेणी अर्थात उद्यम (30 पुरस्कार) तथा ईकोसिस्टम निर्माता (6 पुरस्कार) में 36 पुरस्कार दिए गए थे। विजेताओं को एमएसडीई द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र, दिल्ली में आयोजित शानदार पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया तथा ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र तथा 5 लाख रुपए (उद्यमियों/व्यक्तियों) और 10 लाख रुपए (संगठनों/संस्थानों) का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया था।

(ख) एमएसडीई ने मौजूदा आजीविका गतिविधियों को पुन: आरंभ करके तथा/अथवा मौजूदा उद्यमों का स्तर बढ़ाकर चुने गए शहरों में उद्यमशील गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के छह पवित्र शहरों (पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, कोल्लूर, पंढरपुर और बौध गया) में उद्यमशीलता विकास पर एक परियोजना तैयार की है।

(ग) एमएसडीई, भारत सरकार और जर्मन जनवादी गणतंत्र के संघीय शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आशय की संयुक्त घोषणा पर 01 नवंबर, 2019 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(घ) जर्मन जनवादी गणतंत्र के संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मंत्रालय और सिमेन्स लिमिटेड, भारत एवं एमएसडीई, भारत सरकार के बीच उचित मॉडलों के माध्यम से दोहरी वीईटी (व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण) पहलों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में आशय की संयुक्त घोषणा पर 01 नवंबर, 2019 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(ड.) भारत-जर्मनी व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईजी-वीईटी परियोजना) के क्षेत्र में एमएसडीई, भारत सरकार और डॉयचे गेलशेचाफ्ट फॉर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच, जर्मनी के बीच 08 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में अनुपूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(च) एमएसडीई, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र कौशल परिषद (टीएचएसएससी) के अधिकारियों की उपस्थिति में पर्वतारोहण और साहसिक गितविधियों से संबंधित कौशलीकरण के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 06 नवंबर, 2019 को एमएसडीई में एक

बैठक का आयोजन किया गया था। विचार किए गए विभिन्न मुद्दों में पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों से संबंधित चुनिंदा जॉब रोलों संबंधी आरपीएल कार्यक्रमों को पीएमकेवीवाई (2016-20) के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। आईएमएफ के परामर्श से टीएचएसएससी पीएमकेवीवाई (2016-2020) के सीएससीएम घटक के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आरपीएल संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। सहज कौशलीकरण और उद्यमशीलता का अंग्रेजी, नियोजनीयता और उद्यमशीलता (3ई) मॉड्यूल आरपीएल कार्यक्रम का अभिन्न अंग होंगे। रक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थान इस आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत ऑन बोर्ड होने चाहिए। आईएमएफ पर्वतारोहण और साहस से संबंधित क्षेत्र में पेशेवर निकाय बनाने के लिए विचारों के अंकुरण का बीजारोपण शुरू करेगा।

(छ) <u>जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के अंतर्गत प्रगति</u>: जेएसएस पाठ्यक्रमों के लिए अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणी के लाभार्थियों के अलावा दिव्यांगजन तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों अर्थात बीपीएल के लिए भी शुल्क माफ कर दिया गया है। स्थानीय पारंपरिक कौशलों का संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सभी जेएसएस से कम से कम एक स्थानीय पारंपरिक कौशल की पहचान करने और ऐसे कौशलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बेच चलाने के लिए कहा गया है।

(ज) <u>आजीविका के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति:</u> संकल्प कार्यक्रम से संबंधित हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना स्क्रीनिंग समिति की पांचवी बैठक आयोजित की गई। संकल्प परियोजना के प्रयासों और संचालन के लिए कार्यक्रम अनुमोदन/मूल्यांकन बोर्ड की पांचवी बैठक आयोजित की गई। राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) बेसलाइन की स्थिति और संकल्प के अंतर्गत राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग की गई। छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को राज्य प्रोत्साहन अनुदान जारी किया गया। प्रथम दो वर्षों के लिए संवितरण संबद्ध संकेतकों (डीएलआई) 1 और 4 की उपलब्धियों का सत्यापन स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा किया गया और सत्यापन रिपोर्ट को 17,767,173 अमरीकी डॉलर की राशि उन्मोचित करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझा किया गया।

****